खाकी

योगी की एनकाउंटर नीति से किनारा करने का समय

विकास नारायण राय

खालिस प्रशासनिक नजरिये से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की हाई सिक्यूरिटी रगौली जेल में इस शुक्रवार को हुए शूटआउट में तीन कुख्यात अपराधियों के जान गंवाने को गैंगवार की एक कड़ी और जेल-सुरक्षा में सेंध का मामला कहना ही उचित लगेगा। कम से कम योगी सरकार इस सनसनीखेज वारदात की घोषित जांच को इन्हीं आयामों तक सीमित रखना चाहेगी। जबकि, दरअसल, इस अवसर पर स्वयं उनके शासन की बहुप्रचारित एनकाउंटर नीति के प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर पड़े विपरीत प्रभाव के पेशेवर विश्लेषण की जरूरत है।

दो टूक शब्दों में कहा जाए तो आपराधिक तत्वों से सख्ती के नाम पर होने वाले योगी पुलिस के नियमित एनकाउंटर महज आंकड़ों और सनसनी का राजनीतिक खेल बन कर रह गए हैं। जैसा कि योगी कैम्प का दावा था, ये न शातिर अपराधियों को नियंत्रित करने का उपकरण बन सके और न आम लोगों में सुरक्षा की भावना भर पाने का माध्यम। चित्रकूट शूटआउट का एकमात्र सन्देश यही हो सकता है कि जब योगी के 'सख्त' जेल अनुशासन तक में दुर्दांत अपराधी भी एक-दूसरे से सुरक्षित नहीं, तो जेलों के बाहर छुट्टे घूमते उन बेखौफ असामाजिक चरित्रों के सामने आम जन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? सच्चाई यह है कि एनकाउंटर का हौव्वा जितना भी खड़ा किया जा रहा हो, अपराध पर इसका असर हवाई है। जेलों में बंद रहकर भी गैंगस्टर अपना बाहर का धंधा बदस्तूर चला रहा है।

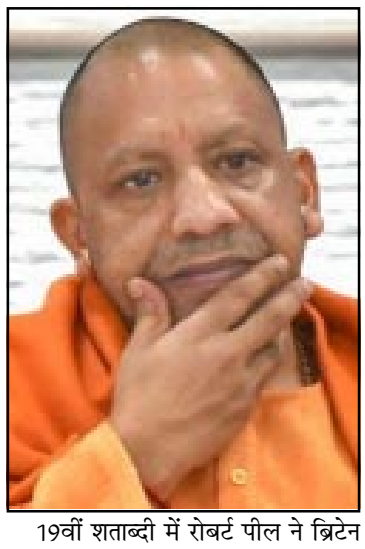

19वीं शताब्दी में रोबर्ट पील ने ब्रिटेन में आधुनिक पुलिसिंग की नींव परस्पर विश्वास की इस घोषणा पर आधारित की थी कि पुलिस पब्लिक है और पब्लिक पुलिस है। यानी, एक सफल कानून-व्यवस्था के लिए दोनों एक-दूसरे के अनिवार्य पूरक हुए। आज भी वहां पुलिस सामान्यत: निहत्थी ड्यूटी करती दिखेगी और उसके एनकाउंटर प्रसंग विरले ही कभी नजर आयेंगे। क्योंकि पुलिस ?ानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं का सम्मान करती है, कानून-सम्मत लोग भी पुलिस का सम्मान करते हैं। इससे से भी बढ़कर, क्योंकि पुलिस और कानून एक पाले में खड़े होते हैं, उनकी सम्मिलित शक्ति के सामने कानून तोड़ने वाला भी हिंसक होने का रास्ता कम ही चुनता है। अपराधी का सामना करने वाली पुलिस की वैधानिकता ही उसकी असल शक्ति है न कि उसकी एनकाउंटर क्षमता। इसीलिए ब्रिटिश पुलिस की गिनती विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुलिस में की जाती है।

क्या इस परिप्रेक्ष्य में चित्रकूट जेल में मुकीम, अंशु और मेराज के शूटआउट से सबक हासिल नहीं किये जाने चाहिए? ये तीन नौजवान गैंगस्टर अलग-अलग आपराधिक पृष्ठभूमि और गिरोहों से थे। मुकीम शामली से, अंशु सीतापुर से, मेराज गाजीपुर से। लेकिन तीनों का एक जैसा दुस्साहसिक इतिहास था। मेराज को गाजीपुर के डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ा बताया गया है और यह भी कि उसे गोली मारते हुए अंशु ने चिल्ला कर कहा था कि मुख्तार अंसारी का हर साथी मार दिया जाएगा। फिलहाल बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अभी महीने भर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब की जेल से स्थानांतरित करा कर लायी है। योगी सरकार को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश हासिल करना प ?ा क्योंकि यूपी पुलिस के हाथों एनकाउंटर की आशंका से डरा हुआ अंसारी अपने राजनीतिक रसूख के दम पर पंजाब की जेलों को सुरक्षित पनाहगाह की तरह इस्तेमाल कर रहा था।

योगी के प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले पूर्व सांसद अंसारी को पूर्वांचल की साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में उनका कट्टर प्रतिद्वंद्वी कहा जाता रहा। निश्चित ही अंसारी के सामने योगी के निशाने पर रहे पूर्वांचल के एक और डॉन मुन्ना बजरंगी की जुलाई 2018 में बागपत जेल में गैंगस्टर सुनील राठी द्वारा गोली मारकर प्रायोजित हत्या का प्रसंग भी रहा होगा। और यूपी पुलिस का वह छद्म-कानूनी आतंक भी जो, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान के बावजूद, जुलाई 2020 में कानपुर के कॉप किलर विकास दुबे के हिरासत में एनकाउंटर से अर्जित किया गया था। बजरंगी को समय-समय पर विभिन्न राजनेताओं ने इस्तेमाल किया था जबकि विकास दुबे स्वयं कानपुर पुलिस का ही गढ़ा भस्मासुर निकला था। ऐसे में, सवाल इतना ही नहीं बनता कि अन्सरियों, बजरंगियों और दूबों से चित्रकूट शूटआउट की जांच को जोड़ कर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए या नहीं। बल्कि, क्या शासन को कानून-व्यवस्था के लिए व्यर्थ सिद्ध हुयी एनकाउंटर नीति से पूरी तरह किनारा नहीं कर लेना चाहिए?

पुलिस की प्राय: एक जायज शिकायत यह रहती है कि लोग स्वत: कानून की पालना नहीं करते और उसे अपने संसाधनों को जाया करना पड़ता है। लेकिन पुलिस का नेतृत्व यह भूल जाता है कि लोग पुलिस को हमेशा कानून के साथ खड़ा नहीं पाते और, लिहाजा, खुद भी कानून के साथ वही करते हैं जो वह कानून के रक्षकों को करते देखते हैं।

एक आदतन अपराधी जो बेशक कानून की उल्लंघना पर उतारू जीव होगा, उसके भी कानून और पुलिस के सम्मिलन से ही नत मस्तक होने की संभावना ज्यादा होती है; अनुभव / रिसर्च का निचोड़ है कि कानून पर अविश्वास जताने वाली पुलिस अपराधी को और दुस्साहसी बनाने में ही उत्प्रेरक सिद्ध होगी।

बहुत समय नहीं हुआ जब सभ्य समाजों में पैदाइशी अपराधी की अवधारणा भी मान्य थी। भारत में इसे 'पूर्व जन्म के फल' सिद्धांत के विस्तार से भी तार्किकता मिली होगी। इटली के मशहूर अपराधशास्त्री शेजारे लोम्ब्रोजो ने 1870 के दशक में इस अवधारणा के समर्थन में अपनी किताब 'क्रिमिनल मैन' के पांच संस्करण प्रकाशित किये। उन्हें बाकायदा हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की छान-बीन में सहायता के लिए आमंत्रित किया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे अपराध और अपराधी की सामाजिकता पर मनुष्य का ध्यान केन्द्रित होता गया। दोस्तोवस्की का उपन्यास 'क्राइम एंड पनिशमेंट' (1866) और टॉलस्टॉय का उपन्यास 'रेजरेक्शन' (1899) इसके सर्वोत्तम उदाहरण बन गए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद के 'गबन' (1931) को भी इस नजरिये से देखा जा सकता है। सार यह कि आधुनिक समाजों में नैतिक मूल्यों और बाह्य परिस्थितियों के अंतर सम्बन्ध अपराधशास्त्र और न्यायशास्त्र की अवधारणाओं को संचालित करने लगे हैं। क्या कोई भी पुलिस इनसे अछूती रह सकती है?

आज अमेरिका में नस्ली पुलिसिंग को लेकर व्यापक आक्रोश है। इसी तरह योगी के यूपी में प्राय: मानवाधिकार समूहों द्वारा सवाल उठाया जाता रहा है कि पुलिस एनकाउंटर में ज्यादातर मुस्लिम और यादव ही क्यों निशाने पर होते हैं? ये किसी भी आधुनिक समाज के दाग और धब्बे हैं। दरअसल, 'कानून का शासन' की व्यवहारिकता पर फलती-फूलती कानून-व्यवस्था समाज के मानसिक स्वास्थ्य की अनिवार्य शर्त है। स्वयं पुलिस के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि पुलिस स्वयं को समाज से एलियनेट नहीं कर सकती।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

16 को उदघाटन के बाद कल शाम तक किसानों की सब्सिडी की आड़ में खाद कंपनियों को पहुँचाया फ़ायदा

घनश्याम सोनी/नवनीत चतुर्वेदी

सरकार ने 19 मई को अपने एक ही फ़ैसले से किसानो को भी खुश कर दिया और उद्योगपतियों को भी । लेकिन देश के लोग सरकार की इस कुत्सित मानसिकता को नहीं समझ सके।

डीएपी खाद का रेट 1200 रुपय था। सरकार ने कुछ दिन पहले उसे 1900 रुपये कर दिया था। हंगामा हुआ तो सरकार ने आज उसका रेट 2400 रुपये करके वापस 1200 रुपये कर दिया ।

अब किसानों को डीएपी 1200 रुपये का मिलेगा और सब्सिडी भी हर बैग पर 1200 होगी जो उद्योगपतियों के खाते में जाएगी ।

इससे देखा जाए तो किसानो को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्हें तो उसी रेट पर डीएपी मिल गया जिस रेट पर वो खरीद रहे थे लेकिन टैक्स भरने वालों का पैसा सब्सिडी के रूप में उद्योगपतियों के पास पहुँच गया ।

सब्सिडी के नाम पर लगभग 14000 करोड़ का फायदा सीधे बड़ी कंपनियों के नाम कर दिया।

जिसके खून में व्यापार हो वो कुछ भी करे, भला उद्योगपतियों का ही होता है ।

किसानों की इस कथित सब्सिडी की आड़ में उन्हें भी शेयर मार्केट के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाया गया। इसे सफ़ेदपोश आर्थिक अपराध कहा जाता है। जिसे आप देख समझ कर महसूस कर सकते हैं लेकिन कभी साबित नही कर सकते। यही वो मूल मंत्र है जिसकी वजह से आज जिला स्तर पर भाजपा का फाइव स्टार ऑफिस है और हर चुनाव में हजारो करोड़ फूंके जाते है।

तीन तस्वीरों के ज़रिए इस सब्सिडी फ़्रॉड को समझिए-

तस्वीर -1 यहां आपको 20 मई दोपहर करीब 12बजे के अनुसार देश की टॉप फ़र्टिलाइज़र कंपनियों के शेयर प्राइस दिख रहे है, कमोबेश सभी कंपनी के शेयर में उछाल आया दिख रहा है, क्योंकि कल ही खाद कंपनियों को 14775 करोड़ की सब्सिडी का एलान हुआ है ।

तस्वीर -2 यहां सैंपल की तर्ज पर गुजरात की एक फर्टिलाइजर कंपनी जीएसएफसी का मौजूदा मार्केट कैप राशि बताया गया है, जो करीब 4800 करोड़ का है वो, जहां लाल निशान से मार्क किया गया है इसको।

तस्वीर 3 यहां इस सैंपल जीएसएफसी कंपनी का पिछले 15 दिनों का शेयर बाजार का रेट दिखाया हुआ है। देखिए लास्ट 15 दिनों से इसके शेयर उछलते हुए 95 रुपए से 122 तक आ पहुँचे है।

19 मई की गई घोषणा से 20 मई को दिन में करीब 5 रुपए का उछाल है। यदि इस 5 रुपये के उछाल से इस कंपनी का एक दिन का फायदा देखा जाए तो करीब 200 करोड़ एक दिन में कमाए हैं। यदि इस कैलकुलेशन को आप पिछले 15 दिनों की लगातार उछाल से देखे तो अब तक इस कंपनी के शेयर्स के दाम में ओवरऑल मिनिमम 1000 करोड़ का उछाल आया है।

अब ये हाल सिर्फ एक सैंपल कंपनी का है, आपको यही ट्रेंड कमोबेश हर फर्टिलाइजर कंपनी में देखने को मिलेगा।

अब सवाल यह उठता है क्या यह संयोग है ??

आखिर प्रधानमंत्री को अचानक से किसानों का भला करने का विचार क्यों आया ?

क्यों सोशल मीडिया व मेनस्ट्रीम मीडिया में खाद की बढ़ी हुई कीमत को जोर शोर से दिखाया गया ? पहले आम जनता में किसानों को पीड़ित मजबूर दिखाया गया कि खाद की बढ़ी हुई कीमत किसानों के साथ अन्याय धोखा है वो अब क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? उसके बाद उन्हें राहत देने के लिए वो अचानक सब्सिडी एलान कर देते है।

इसके बाद खाद सब्सिडी राहत पैकेज को क्यों जोर शोर से मार्केटिंग की गई ?

इन सब का कनेक्शन यहां स्टॉक मार्केट से कैसे जुड़ रहा है!!

फर्टिलाइजर कंपनी को हुए प्रॉफिट में से यदि इलेक्टोरल बांड खरीद लिया जाए तो किसी को क्या पता चलेगा ?

आखिर क्यों सब्सिडी का पैसा किसानों को सीधे उनके अकाउंट में नही दिया जा रहा है ?

Date	Open	High	Low	Close*	
20-May-2021	124.70	124.70	120.70	121.20	1
19-May-2021	118.35	119.55	117.00	117.85	1
18-May-2021	121.00	122.25	118.00	118.85	1
17-May-2021	116.30	121.45	115.30	119.20	1
14-May-2021	116.00	121.30	114.00	115.65	1
12-May-2021	118.00	119.90	112.05	114.15	1
11-May-2021	111.80	117.65	110.55	116.50	1
10-May-2021	105.10	113.85	104.15	112.30	1
07-May-2021	101.45	105.70	100.40	103.95	1
06-May-2021	97.55	102.40	96.95	100.50	1
05-May-2021	95.45	97.65	93.85	96.55	
04-May-2021	95.00	98.25	92.55	93.15	

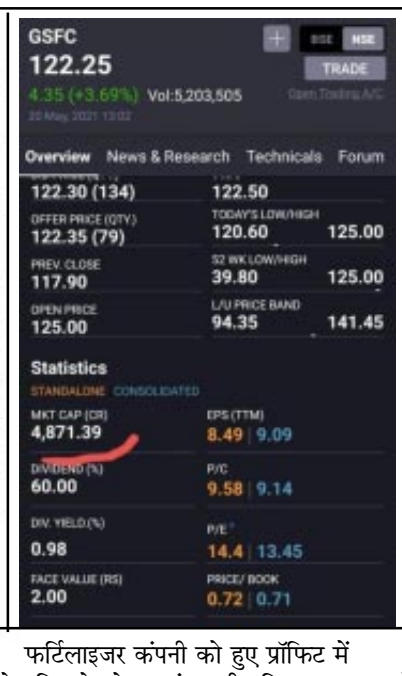

Fertilizers

Company Name	Last Price	% Chg
Coromandel Int	808.15	4.34
Tata Chemicals	710.40	-0.31
Chambal Fert	294.10	3.25
Fert and Chem	131.85	4.93
GNFC	391.40	1.08
GSFC	122.65	4.07
Rashtriya Chem	85.10	5.26
NFL	89.85	6.32
Deepak Fert	296.25	3.51
Mangalore Chem	94.20	2.06
SPIC	46.75	0.75
Nagarjuna Fert	10.38	4.95
Madras Fert	30.65	4.97
Zuari Agro Chem	99.70	1.94
Rama Phosphates	175.20	5.35
Zuari Global	94.40	0.96
Aries Agro	111.55	-0.27
Basant Agro Tec	10.30	6.51
Bharat Agri	165.15	2.77

आपने बच्चों की फ़ीस, घर का राशन, अस्पताल का बिल भरने के लिए जैसे ही ज़ेवर बेचने शुरू किए । सरकार ने पुराने ज़ेवर बेचने पर जीएसटी लगा दी ।